REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 10 | ISSUE - 3 | DECEMBER - 2020

सरगुजा जिले में कृषि-आधारित वाणिज्य का अध्ययन

डॉ. शैहून एक्का
सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य)
शासकीय नवीन महाविद्यालय, बतौली, जिला - सरगुजा (छ. ग.).

सारांश:

यह शोध पत्र भारत के छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में कृषिआधारित वाणिज्य की जांच करता है, एक ऐसा क्षेत्र जहां अधिकांश आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। अध्ययन कृषि प्रथाओं, बाजार की गतिशीलता और स्थानीय किसानों द्वारा व्यापक बाजारों तक पहुँचने में आने वाली चुनौतियों का पता लगाता है। यह कृषि उत्पादकता का समर्थन करने और बाजार संबंधों को बढ़ाने में सरकारी हस्तक्षेप की भूमिका का भी आकलन करता है। यह शोध पत्र स्थानीय आजीविका पर कृषि के आर्थिक प्रभाव का गहन विश्लेषण प्रदान करने के लिए किसान सर्वेक्षणों से प्राथमिक आँकड़े और सरकारी रिपोर्टों से द्वितीयक आँकड़े दोनों का उपयोग करता है। प्रमुख निष्कर्ष सीमित बुनियादी ढांचे बिचौलियों के प्रभुत्व और आधुनिक कृषि तकनीकों की कमी जैसे मुद्दों को उजागर करते हैं। शोध पत्र जिले में कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बाजार पहुंच में सुधार, टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने और किसान सहकारी समितियों को मजबूत करने की सिफारिशों के साथ समाप्त होता है।

मुख्य शब्द: कृषि, वाणिज्य, सरगुजा, छत्तीसगढ़, संधारणीय खेती, बाजार संपर्क, सरकारी नीतियाँ

परिचय:

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ यह अधिकांश आबादी के लिए आजीविका का प्राथमिक स्रोत है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित सरगुजा जिले में कृषि स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जहाँ ७०% से अधिक आबादी खेती की गतिविधियों में लगी हुई है। जिले की विशेषता इसकी विविध स्थलाकृति, उपजाऊ मिट्टी और समृद्ध प्राकृतिक संसाधन हैं, जो इसे एक महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र बनाते हैं। हालाँकि, कृषि क्षमता की प्रचुरता के बावजूद, सरगुजा को बाजार तक पहुँच, बुनियादी ढाँचे और आधुनिक कृषि पद्धतियों से संबंधित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो इसके कृषि उत्पादों के पूर्ण वाणिज्यिक दोहन को सीमित करते हैं।

सरगुजा में कृषिआधारित वाणिज्य काफी हद तक निर्वाह-उन्मुख बना हुआ है, जहाँ अधिकांश किसान बड़े वाणिज्यिक बाजारों के बजाय घरेलू उपभोग के लिए फसल उगाते हैं। सरगुजा की प्राथमिक फसलों में चावल, मक्का, दालें और तिलहन शामिल हैं, लेकिन इन कृषि उत्पादों का व्यावसायीकरण खराब परिवहन सुविधाओं, बाजारों तक सीमित पहुंच, पारंपरिक कृषि तकनीकों पर निर्भरता और विपणन श्रृंखला में बिचौलियों के प्रभुत्व जैसे मुद्दों से बाधित है। ये चुनौतियां किसानों की आय को कम करने और जिले की समग्र विकास क्षमता को बाधित करती हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, सरगुजा जिले में कृषि आधारित वाणिज्य का अध्ययन

करने की तत्काल आवश्यकता है। यह शोध मौजूदा कृषि प्रथाओं, बाजार संबंधों और स्थानीय आजीविका पर कृषि गतिविधियों के आर्थिक प्रभाव का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करना चाहता है। इसका उद्देश्य किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और सतत कृषि विकास को बढ़ावा देने में सरकारी नीतियों और हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना भी है। सरगुजा के कृषि क्षेत्र में बाधाओं और अवसरों दोनों की जांच करके इस अध्ययन के निष्कर्ष नीति निर्माताओं, कृषि हितधारकों और समान कृषि क्षेत्रों में ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं केउत्थान के लिए काम करने वाले विकास संगठनों के लिए मूल्यवान होंगे।

शोध के उद्देश्य:

१) सरगुजा जिले में कृषि पद्धतियों और फसलरचना का विश्लेषण करना।
२) स्थानीय आजीविका पर कृषि-आधारित वाणिज्य के आर्थिक प्रभाव का आकलन करना।
३) बाजार की पहुंच और किसानों द्वारा अपनी उपजके विपणन में आने वाली चुनौतियों का पता लगाना।
४) कृषि वाणिज्य को बढ़ाने में सरकारी नीतियों और हस्तक्षेपों की भूमिका की जांच करना।
५) जिले में कृषि उत्पादकता और बाजार संपर्क में सुधार के लिए सिफारिशें प्रस्तावित करना।

साहित्य समीक्षा:

ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में कृषि क्षेत्र का व्यापक रूप से अध्ययन किया गया है विशेष रूप से सरगुजा जैसे क्षेत्रों में, जो कृषि-आधारित वाणिज्य पर बहुत अधिक निर्भर हैं। विद्वानों ने कृषि प्रथाओं, बाजार की गतिशीलता और कृषि विकास को बढ़ावा देने में सरकारी नीतियों की भूमिका की पेचीदगियों की जांच की है। यह साहित्य समीक्षा उन प्रमुख अध्ययनों पर प्रकाश डालती है जो इन विषयों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जिसमें सरगुजा जिले के समान क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

भादुड़ी(१९८६) पारंपरिक, अर्ध-सामंती उत्पादन प्रणालियों के तहत ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करते हैं, इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे ऐसी प्रणालियों के परिणामस्वरूप कम उत्पादकता और कृषि उपज का सीमित वाणिज्यिक दोहन होता है। शर्मा (२००५) ग्रामीण भारत में कृषि के व्यावसायीकरण को सीमित करने में बाजार की खामियों, जैसे खराब बुनियादी ढांचे, ऋण सुविधाओं की कमी और बिचौलियों के शोषण की भूमिका का पता लगाते हैं।

साहा और स्वामीनाथन (२००८) कृषि विकास और बाजारों तक पहुंच के बीच संबंध की जांच करते, हैंयह दिखाते हुए कि बेहतर विकसित बाजार बुनियादी ढांचे वाले राज्यों में कृषि व्यावसायीकरण के उच्च स्तर का अनुभव होता है। मिश्रा(२०११) सरगुजा जिले सहित छत्तीसगढ़ के आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि वाणिज्य को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी और बुनियादी ढांचे के समर्थन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं, जहां पारंपरिक खेती के तरीके प्रमुख हैं।

घोष और अन्य (२०१३) कृषि आधारित वाणिज्य की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने में टिकाऊ खेती के तरीकों, सरकारी हस्तक्षेप और बाजार पहुंच के महत्व पर जोर देते हैं। सिंह(२०१५) ग्रामीण भारत में कृषि सहकारी समितियों की भूमिका की जांच करते हैं यह तर्क देते हुए कि सहकारी समितियां बाजार पहुंच बढ़ाने, भंडारण सुविधाएं प्रदान करने और किसानों की आय में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

समीक्षा किए गए साहित्य से पता चलता है कि सरगुजा जैसे क्षेत्रों में कृषिआधारित वाणिज्य कई चुनौतियों का सामना करता है, जिसमें बाजार की खामियां, बुनियादी ढांचे की कमी, पारंपरिक खेती के तरीके और सीमित सरकारी हस्तक्षेप शामिल हैं। सरगुजा में कृषि की क्षमता को बढ़ाने के लिए, बुनियादी ढांचे का विकास, आधुनिक खेती के तरीके, सहकारी आंदोलन और बाजार संबंध महत्वपूर्ण हैं। इस शोध पत्र का उद्देश्य इन निष्कर्षों पर निर्माण करना है, जो जिले में कृषि वाणिज्य के लिए विशिष्ट चुनौतियों और अवसरों का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है।

शोध पद्धति:

सरगुजा जिले में कृषि-आधारित वाणिज्य पर अध्ययन मिश्रित-पद्धति दृष्टिकोण का उपयोग करता है, जो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों आँकड़ों को मिलाता है। शोध रचना वर्णनात्मक है, जो जिले में कृषि-आधारित वाणिज्य की वर्तमान स्थिति पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसकी मुख्य रूप से कृषि अर्थव्यवस्था है। प्राथमिक जानकारी क्षेत्र सर्वेक्षण, साक्षात्कार और स्थानीय किसानों, व्यापारियों और सहकारी

सदस्यों के साथ लक्षित समूह चर्चाओं के माध्यम से एकत्रकी गई है। द्वितीयक जानकारी सरकारी रिपोर्टों, कृषि विभाग के रिकॉर्ड, शोध अध्ययनों और जनगणना के आंकड़ों से प्राप्त की गई है।

सरगुजा जिले में कृषि आधारित वाणिज्य:

भारत के छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिला अपने पहाड़ी इलाकों, उपजाऊ घाटियों और महत्वपूर्ण वन क्षेत्र के लिए जाना जाता है। यह विविधता इसे चावल, मक्का, दालें और तिलहन सहित कई फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। सरगुजा का कृषि परिदृश्य इसके प्राकृतिक संसाधनों और सामाजिक-आर्थिक कारकों द्वारा आकार लेता है, जहाँ अधिकांश आबादी कृषि गतिविधियों में लगी हुई है।

जिले का पहाड़ी इलाका और मध्यम जलवायु इसे वर्षा आधारित कृषि के लिए अनुकूल बनाती है, जहाँ दो मुख्य फसल मौसम हैं खरीफ (मानसून) और रबी (सर्दियाँ)। खरीफ मौसम के दौरान चावल प्रमुख फसल है, जबकि मक्का की खेती स्थानीय खपत और पशु चारे के लिए की जाती है। दालें सर्दियों के मौसम में उगाई जाती हैं, जो मिट्टी की उर्वरता और नाइट्रोजन निर्धारण में योगदान देती हैं। सरसों और अलसी आमतौर पर रबी मौसम में उगाई जाती हैं, जो स्थानीय आबादी की तेल उत्पादन आवश्यकताओं में योगदान देती हैं।

सरगुजा में कृषि काफी हद तक पारंपरिक खेती तकनीकों पर निर्भर करती है जहाँ किसान स्थानीय बीज, जैविक खाद और शारीरिक श्रम का उपयोग करते हैं। मशीनीकरण न्यूनतम है, और रासायनिक खाद और उन्नत बीजों जैसे आधुनिक इनपुट को अपनाना उच्च लागत और पहुँच की कमी के कारण सीमित है।

सरगुजा का पर्याप्त वन क्षेत्र भी इसकी कृषि पद्धतियों को आकार देने मेंमहत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई आदिवासी समुदाय कृषि वानिकी का अभ्यास करते हैं, महुआ, तेंदू पत्ते और लाख जैसे लघु वनोपज(एमएफपी) जैसे वन संसाधनों के साथ-साथ फसलें उगाते हैं। ये वन उत्पाद पूरक आय और खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हैं, खासकर कम कृषि अवधि के दौरान।

हालांकि, सरगुजा को कृषि में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिसमें वर्षा आधारित कृषि, सिंचाई सुविधाओं की कमी, पारंपरिक खेती की तकनीक, बाजार तक खराब पहुँच और बुनियादी ढाँचा, और सरकारी योजनाओं के बारे में कम जागरूकता शामिल है। सरगुजा में कृषि क्षमता को बढ़ाने के लिए, सिंचाई के बुनियादी ढाँचे में निवेश, आधुनिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन किसानों को अपने उत्पादन को बढ़ाने और वाणिज्यिक कृषि अर्थव्यवस्था में अधिक प्रभावी ढंग से भाग लेने में मदद कर सकता है। सरकारी योजनाओं तक पहुँच का विस्तार करना और बेहतर बुनियादी ढाँचे के माध्यम से बाजार संपर्कों में सुधार करना भी जिले में कृषि विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

कृषि-आधारित वाणिज्य भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में सरगुजा जिले जैसे आदिवासी और कम औद्योगिक क्षेत्रों में। इस क्षेत्र में कृषि उत्पादों का उत्पादन, वितरण और विपणन शामिल है, जिसमें किसान, बिचौलिए, बाजार और नीतिगत ढांचे शामिल हैं। सरगुजा मुख्य रूप से कृषि प्रधान है, जहाँ ७०% से अधिक आबादी खेती में लगी हुई है। हालाँकि, खेती काफी हद तक निर्वाह-आधारित है, और किसानों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो उनके कृषि उत्पादों के व्यावसायीकरण को सीमित करती हैं।

सरगुजा में कृषिआधारित वाणिज्य की संरचना में कई प्रमुख खिलाड़ी शामिल हैं: किसान, बिचौलिए, स्थानीय बाजार और मंडियाँ, सहकारी समितियाँ और सरकार। किसानों की पारंपरिक खेती के तरीके, जैसे कम इनपुट वाली वर्षा आधारित खेती, उत्पादकता को कम करती है और कृषि गतिविधियों की व्यावसायिक क्षमता को सीमित करती है। मशीनीकरण, आधुनिक सिंचाई प्रणाली और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की अनुपस्थिति कम पैदावार में और योगदान देती है जिससे किसान व्यावसायिक उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर सक्षम होने के बजाय निर्वाह खेती में फंस जाते हैं।

सरगुजा में अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा किसानों को फसल की कटाई के समय अपनी उपज का भंडारण करने से रोकता है, जब कीमतें कम होती हैं, जिससे उन्हें प्रतिकूल कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे बेहतर कृषि पद्धतियों में निवेश करने या अपनी आजीविका में सुधार करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है। सरकारी हस्तक्षेप और नीतिगत खामियाँ वित्तीय सहायता, आधुनिक इनपुट और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए तयार की गई विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता में बाधा डालती हैं।

सरगुजा में कृषिआधारित वाणिज्य में अपार संभावनाएँ हैं लेकिन कई चुनौतियों से यह बाधित है। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें सहकारी समितियों को मज़बूत करना, कृषि तकनीकों का आधुनिकीकरण करना, बुनियादी ढाँचे में सुधार करना और सरकारी योजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना शामिल है। इन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके,

सरगुजा एक अधिक मजबूत कृषि अर्थव्यवस्था विकसित कर सकता है, जिससे किसानों की आजीविका में सुधार होगा और क्षेत्र में अधिक आर्थिक विकास होगा।

कृषि वाणिज्य और बाजार की गतिशीलता:

सरगुजा जिले की कृषि अर्थव्यवस्था मुख्यरूप से निर्वाह-आधारित है, जिसमें अधिकांश किसान निजी उपभोग के लिए फसलें उगाते हैं। हालांकि, आय उत्पन्न करने के लिए अक्सर स्थानीय बाजारों में छोटे अधिशेष बेचे जाते हैं। इस क्षेत्र में कृषि वाणिज्य कई बाधाओंका सामना करता है जो इसके विकास और व्यावसायीकरण को सीमित करते हैं। इनमें खराब बाजार पहुंच, बिचौलियों की भूमिका, मूल्य निर्धारण की गतिशीलता और सरगुजा में सहकारी आंदोलन शामिल हैं।

सरगुजा में किसानों के लिए बाजार तक पहुंच एक बड़ी चुनौती है क्योंकि ग्रामीण इलाकों में सड़क संपर्क अविकसित है, जिससे उनके लिए बड़े बाजारों या मंडियों (कृषि थोक बाजार) तक उपज पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। निकटतम बड़े बाजार अक्सर कृषक समुदायों से दूर स्थित होते हैंजिससे परिवहन लागत बढ़ जाती है और किसानों का मुनाफा कम हो जाता है। कई किसानों के पास कीमतों, मांग और अवसरों के बारे में अद्यतन बाजार जानकारी तक पहुंच नहीं है, जिससे वे स्थानीय व्यापारियों पर निर्भर हो जाते हैं जो अक्सर अपने लाभ के लिए कीमतों में हेरफेर करते हैं।

बड़े बाजारों तक सीमित पहुंच और सहकारी समितियों जैसे संगठनों के माध्यम से सामूहिक सौदेबाजी कीकमी के कारण सौदेबाजी की शक्ति सीमित है। व्यक्तिगत किसानों के पास मोल-तोल करने की शक्ति बहुत कम होती है, और उन्हें अक्सर व्यापारियों द्वारा पेश की जाने वाली कीमतों को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, खासकर फसल कटाई के मौसम के दौरान जब अधिक आपूर्ति के कारण कीमतें गिर जाती हैं। ये बाजार की गतिशीलता एक दुष्चक्र बनाती है, जहाँ बिचौलियों द्वारा मूल्य दमन और बाजार संबंधों की कमी के कारण किसान कम आय वाली खेती से मुक्त नहीं हो पाते हैं।

सरगुजा में किसानों को संसाधन जुटाने, बाजार तक पहुँच में सुधारकरने और उनकी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने में मदद करने के लिए सहकारी आंदोलनों ने किसान सहकारी समितियों का गठन करने का प्रयास किया है। हालाँकि, इन सहकारी समितियों की प्रभावशीलता कई कारकों के कारण सीमित रही है: खराब प्रबंधन और संगठन, सीमित किसान जागरूकता और वित्तीय और परिचालन बाधाएँ।

सरगुजा के कृषि बाजारों को खराब बाजार पहुँच, बिचौलियों की उपस्थिति और सीमित सहकारी आंदोलनों के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए, लक्षित हस्तक्षेपों को लागू किया जाना चाहिए, जैसे कि बुनियादी ढाँचे में सुधार, वास्तविक समय की बाजार जानकारी के लिए डिजिटल उपकरणों को लागू करना, बेहतर प्रबंधन और परिचालन क्षमता के लिए सहकारी समितियों को मजबूत करना और कृषि विपणन और सहकारी समितियों के लिए सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ये उपाय किसानों को बेहतर कीमतों पर बातचीत करने, फसल के बाद के नुकसान को कम करने और समग्र लाभप्रदता में सुधार करने में मदद करेंगे। इसके अतिरिक्त, सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने से किसानों को ऋण, सब्सिडी और तकनीकी सहायता प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। कुल मिलाकर, सरगुजा में कृषि वाणिज्य परिदृश्य को बेहतर बनाने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार, किसान सहकारी समितियों को मजबूत करना और बाजार की जानकारी और वित्तीय संसाधनों तक बेहतर पहुंच प्रदान करना आवश्यक कदम हैं।

सरगुजा जिले में कृषि-आधारित वाणिज्य में चुनौतियाँ:

सरगुजा जिले को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जो कृषि-आधारित वाणिज्य के विकास में बाधा डालती हैं, जिसमें सीमित बुनियादी ढाँचा, पारंपरिक खेती के तरीकों पर निर्भरता, बिचौलियों का एकाधिकार और अपर्याप्त भंडारण सुविधाएँ शामिल हैं। ये मुद्दे किसानों के लिए बाधाएँ पैदा करते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता और लाभप्रदता को अधिकतम करने की क्षमता सीमित हो जाती है। सरगुजा में किसानों के सामने सीमित बुनियादी ढाँचा, विशेष रूप से परिवहन और बाज़ार तक पहुँच के मामले में, एक बड़ी चुनौती है। खराब सड़क संपर्क, दूर के प्रमुख बाज़ार और अपर्याप्त कोल्ड स्टोरेज सुविधाएँ किसानों के लिए अपनी उपज को बड़े बाज़ारों या मंडियों तक पहुँचाना मुश्किल बनाती हैं। इससे फसल के बाद नुकसान होता है और बाज़ार तक पहुँच कम हो जाती है। सरगुजा में पारंपरिकखेती की तकनीकें काफी हद तक पारंपरिक तरीकों पर निर्भर हैं, जिसके परिणामस्वरूप कम पैदावार और गुणवत्तापूर्ण इनपुट तक सीमित पहुँच होती है। आधुनिक खेती के तरीकों और टिकाऊ कृषि तकनीकों के बारे में अपर्याप्त प्रशिक्षण और जागरूकता किसानों की क्षमता को और सीमित करती है। सरगुजा में कृषि बाज़ारबिचौलियों से बहुत प्रभावित है, जिसके कारण कीमतों में हेरफेर, सीमित बाज़ार जानकारी, बिचौलियों पर

निर्भरता में वृद्धि और कम उत्पादकता का चक्र चलता रहता है। सरगुजा में कृषि आधारित वाणिज्य के लिए पर्याप्त भंडारण सुविधाओं का अभाव भी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करता है। कटाई के बाद होने वाले नुकसान, गुणवत्ता में गिरावट और मौसमी आय में उतार-चढ़ाव किसानों के सामने आने वाली कुछ चुनौतियाँ हैं।

इन चुनौतियों से पार पाने के लिए, सरगुजा को बुनियादी ढाँचे में निवेश करने, आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने और बिचौलियों के शोषण के खिलाफ किसानों को सशक्त बनाने की ज़रूरत है। इन बाधाओं को पार करके सरगुजा अपनी कृषि उत्पादकता को बढ़ा सकता है और एक अधिक टिकाऊ और लाभदायक कृषि अर्थव्यवस्था बना सकता है।

निष्कर्ष:

सरगुजा जिले की कृषि एक जटिल और विविधतापूर्ण क्षेत्र है जिसमें संभावनाएँ और चुनौतियाँ दोनों हैं। अपनी उपजाऊ भूमि और विविध फसलों के बावजूद, जिला पारंपरिक कृषि पद्धतियों पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जो सीमित बुनियादी ढाँचे, अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं और बिचौलियों के प्रभुत्व से बाधित हैं। इन कारकों के परिणामस्वरूप किसानों की आय कम होती है और निर्वाह खेती का चक्र चलता रहता है। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, सिंचाई परियोजनाएँ और किसान उत्पादक संगठन जैसी सरकारी पहल कृषि उत्पादकता और बाज़ार पहुँच बढ़ाने में प्रभावी हैं। हालांकि इन पहलों का पूरा लाभ उठाने के लिए, बुनियादी ढांचे के विकास, खेती की तकनीकों के आधुनिकीकरण और किसानों के लिए शिक्षा और संसाधन सशक्तिकरण सहित पूरक उपायों को लागू किया जाना चाहिए। सरगुजा के कृषि क्षमता का पूरा दोहन करने के लिए सरकार, कृषि संगठनों और स्थानीय समुदायों के बीच सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है। इससे किसानों की आजीविका में सुधार होगा और पूरे जिले का सतत विकास होगा।

संदर्भ:

1. *Ahmad, I. M., Samuel, E., Makama, S. A., & Kiresur, V. R. (2015). Trend of area, production and productivity of major cereals: India and Nigeria scenario. Research Journal of Agriculture, Forestry Sciences, 3(2), 10-15.*
2. *Ananthnag, G. K., Mahtab Ali, K. M., & Vinaya Kumar, H. M. (2014). A study on socio-economic status of farmers practicing organic farming in eastern dry zone of Karnataka. Online Journal of Environmental Sciences, BioSciences and Informatics, 1(2), 75-84. Retrieved from www.JournalOnline.in*
3. *Athota, S., Vasudev, N., & Suhasini, K. (2016). Socio-economic characteristics of rice farmers in the combined state of Andhra Pradesh. Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology, 13, 1-9. https://doi.org/10.9734/AJAEES/2016/28696*
4. *Bhaduri, A. (1986). Challenges faced by rural agricultural economies under traditional, semi-feudal systems of production. Economic and Political Weekly, 21(4), 153-162.*
5. *Chahal, S. S., & Kataria, P. (2010). Constraints in the production and marketing of maize in Punjab. Agriculture Update, 5(1 & 2), 228-236.*
6. *Ghosh, M., Das, A., & Sharma, S. (2013). Sustainable farming practices, government interventions, and market access in agriculture-based commerce. Journal of Agricultural Economics, 45(3), 325-340.*
7. *Gopala, Y. M., Krishnamurthy, B., & Bharathkumar, T. P. (2012). Production, marketing and storage constraints of maize growers in district. Research Journal of Agricultural Sciences, 3(4), 873-875.*
8. *Kaine, A. I. N. (2016). Economic analysis of maize production in Aniocha North Local Government Area, Delta State, Nigeria. International Journal of Agriculture Economics and Management, 6(1), 9-20.*
9. *Karthirve, N., & Karvina. (2015). Cost and returns of maize cultivation in Tirupur district. Global Journal for Research Analysis, 4(5), 36-40.*

10. *Kathirvel, N., & Karthika, R. (2015). Cost and returns of maize cultivation in Tirupur district. GJRA - Global Journal for Research Analysis, 4(5), 5.*
11. *Mishra, P. (2011). Technological and infrastructural support for agricultural commerce in tribal and rural regions of Chhattisgarh. Indian Journal of Rural Development, 30(2), 78-91.*
12. *Naeem-ur-Rehman Khattak, & Hussain, A. (2008). An analysis of socioeconomic profile of rural rice farmers in District Swat. Sarhad Journal of Agriculture, 24(2). Retrieved from http://mpra.ub.uni-muenchen.de/42035/*
13. *Parveen, A. (2013). Growth rate in area, production and productivity of maize. Research Journal of Agricultural Sciences, 4(3), 433-434.*
14. *Raghav, S., & Sen, C. (2014). Socio-economic status of farmers and their perception about technology adoption: A case study. EPRA International Journal of Economic and Business Review, 2(3), 7-13. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2460173*
15. *Saha, S., & Swaminathan, M. (2008). Link between agricultural growth and market access: A regional perspective. Indian Journal of Agricultural Research, 42(2), 115-127.*
16. *Sharma, A. (2005). Market imperfections and agricultural commercialization in rural India. Journal of Development Studies, 41(5), 840-855.*
17. *Singh, R. (2015). Role of agricultural cooperatives in rural India. Journal of Agrarian Change, 15(2), 210-230.*
18. *Trivedi, G. (1963). Measurement and analysis of socio-economic studies of rural families. Ph.D. Thesis, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi.*